लैंडलॉक की चुनौती दूर करने के लिए औद्योगिक प्राधिकरणों को दी जिम्मेदारी

लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी किया जा रहा मजबूत, विकसित हो रहे केंद्र

अमर उजाला ब्यूरो

यूपीडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जिम्मेदारियां बांटी गईं

लखनऊ। लैंडलॉक राज्य की चुनौती का सामना कर रहे यूपी ने अब लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को दी है। यूपीडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारियां बांटी गई हैं।

इसके तहत कार्गो कॉम्प्लेक्स और एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स हब, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एमआरओ और कार्गो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक्स केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 14 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी से कम करने के उद्देश्य से मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, एक्सप्रेसवे और उड़ान योजना जैसी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में फैले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह नोड को भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही राज्य ने अपना पहला मेडिकल डिवाइस पार्क लॉन्च किया है। यीडा फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और सेमीकंडक्टर पार्क जैसे औद्योगिक क्लस्टर का विकास कर रहा है।

इसके अतिरिक्त दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, मेरठ–मुजफ्फरनगर निवेश क्षेत्र, दीनदयाल उपाध्याय नगर-वाराणसी-मिर्जापुर क्षेत्र, लखनऊ-उन्नाव-कानपुर क्षेत्र और प्रयागराज-वाराणसी क्षेत्र शामिल हैं। झांसी और औरैया में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा और अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और आगरा में एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं को बनाया जा रहा है।